भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
19.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3128 का उत्तर

कांवट रेलवे स्टेशन पर पैदल पार पुल

3128. श्री अमरा राम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सीकर जिले के कांवट रेलवे स्टेशन पर पैदल पार पुल की कमी के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए पैदल पार पुल स्वीकृत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सीकर संसदीय क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर में कितने स्टेशनों पर पैदल पार पुल नहीं हैं; और

(घ) इसके लिए स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल में स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता,

नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि शामिल हैं और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के सृजन की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1337 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 85 स्टेशन राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में विकास हेतु चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:-

राज्य	अमृत भारत स्टेशनों की संख्या	अमृत भारत स्टेशनों के नाम
राजस्थान	85	आबू रोड, अजमेर, अलवर, अनूपगढ़, असलपुर जोबनेर, बालोतरा, बांदीकुई, बारां, बाड़मेर, बयाना, ब्यावर, भरतपुर, भवानी मंडी, भीलवाड़ा, बिजयनगर, बीकानेर, बूंदी, चंदेरिया, छबड़ा गुगोर, चित्तौड़गढ़ जं., चूरू, डकनिया तलाव, दौसा, डीग, डेगाना, देशनोक, धौलपुर,

		डीडवाना, डूंगरपुर, फालना, फतेहनगर, फतेहपुर शेखावटी, गांधीनगर जयपुर, गंगापुर सिटी, गोगामेड़ी, गोटन, गोविंदगढ़, हनुमानगढ़, हिंडौन सिटी, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, जवाई बांध, झालावाड़ सिटी, झुंझुनू, जोधपुर, कपासन, खैरथल, खेरली, कोटा, लालगढ़, मंडलगढ़, मंडावर महवा रोड, मारवाड़ भीनमाल, मारवाड़ जंक्शन, मावली जंक्शन, मेड़ता रोड, नागौर, नरैना, नीम का थाना, नोखा, पाली मारवाड़, फलौदी, फुलेरा, पिंडवाड़ा, रायसिंह नगर, राजगढ़, रामदेवरा, रामगंजमंडी, राणा प्रतापनगर, रानी, रतनगढ़, रेन, रींगस, सादुलपुर, सांगानेर, सवाई माधोपुर, श्री महावीरजी, सीकर, सोजत रोड, सोमेसर, श्रीगंगानगर, सुजानगढ़, सूरतगढ़, उदयपुर सिटी

सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित तीन (03) रेलवे स्टेशनों यथा नीम का थाना, रींगस और सीकर रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित किया गया है। इन स्टेशनों पर विकास संबंधी कार्यों के लिए निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं और कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

नीम का थाना स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म शेल्टर का प्रावधान से संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा स्टेशन भवन में सुधार, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म की सतह, परिचलन क्षेत्र आदि निर्माण के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

रींगस स्टेशन पर, नए ऊपरी पैदल पुल, स्टेशन भवन में सुधार, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार, प्रतीक्षालय, परिचलन क्षेत्र आदि के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

सीकर स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म शेल्टरों के प्रावधान से संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा नए ऊपरी पैदल पुल के निर्माण, स्टेशन भवन में सुधार, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म की सतह, परिचलन क्षेत्र और लिफ्ट की व्यवस्था आदि से संबंधित कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

भारतीय रेल पर रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन निरंतर चलने वाली सतत् प्रक्रिया है तथा इस संबंध में कार्य परस्पर प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। बहरहाल, कार्यों को स्वीकृत और निष्पादित करते के समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों के विकास/उन्नयन को प्राथमिकता दी जाती है। डाबला और कांवट रेलवे स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुल के प्रावधान के लिए कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इंटर-प्लेटफॉर्म स्थानांतरण सुविधा के लिए कछेरा, किशनमानपुरा और मांवडा रेलवे स्टेशनों में मार्ग मुहैया कराए गए हैं।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए अग्नि संबंधी मंजूरी, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ और उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

सामान्यतः, स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण को योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। जिसमें अमृत भारत स्टेशन योजना भी शामिल है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है। राजस्थान राज्य पांच क्षेत्रीय रेलों नामतः उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5,369 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) का आवंटन किया गया है।

******